फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 74 संख्याः 179 प्रभात जयपुर, मंगलवार 30 जनवरी, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

A CIA Spy Sets up India's First Aircraft Factory

William Douglas Pawley, a go-getting businessman, a middleman, insisting on his commission, and an agent, knew the right people.

Transform Your Look

Make 'Learning' a Part of Your Daily Routine

दिल्ली में 'पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना' के एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करवा कर जयपुर लौटने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का सांगानेर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ।

मुख्यमंत्री भजन लाल का ई.आर.सी.पी. हस्ताक्षर के बाद जयपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत

हस्ताक्षर से उत्साहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिले के लोगों ने मुख्यमंत्री को हवाई अड्डे पर मालाओं से लादा

- **मंत्रिमण्डल के सदस्यों तथा विधायकों ने भी मुख्यमंत्री के विधानसभा पहुंचने पर स्वागत किया और इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिये धन्यवाद दिया।**
- **पच्चीस लाख किसान परिवारों को लाभांवित करने के साथ ही इस क्षेत्र के 26 पूर्वनिर्मित बांधों का भी पुनरोद्धार होगा।**

जयपुर, 29 जनवरी, (का.सं.)। राजस्थान के 13 जिलों के लिए बहुप्रतिक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) पर रविवार को नई दिल्ली में त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षर हुए। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को जब नई दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तब वहां विभिन्न जिलों से आए लोगों ने उनका स्वागत किया और धन्यवाद दिया। इसके बाद शर्मा का विधानसभा पहुंचने पर मंत्रिमंडल सदस्यों और विधायकों ने स्वागत कर धन्यवाद दिया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सभी सदस्यों और 13 जिलों की जनता की तरफ से उन्हें बुके भेंट किया।

मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए लोगों ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर उनकी वर्षों पुरानी आस अब पूरी हुई है।

इससे राज्य के 13 जिलों में 2.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे 25 लाख से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही, औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए भी पानी मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदस्यों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा। राज्य सरकार हर क्षेत्र और हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा सदस्यों ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए यह परियोजना वरदान साबित होगी। सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

उल्लेखनीय है कि ईआरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक के लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, भूजल के स्तर में भी वृद्धि होगी।

एमओयू के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनैरा बैराज, मेज बैराज, राठौड़ बैराज, डूंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डूंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध का क्षमतावर्धन एवं पूर्वनिर्मित 26 बांधों का पुनरूद्धार किया जाएगा।

डॉ. मनमोहन सिंह इस बार की खेप में राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं

पर, काफी अस्वस्थ व कमजोर हैं, कई दिनों से राज्यसभा में भी सत्र के दौरान उपस्थित नहीं रह पाते

- **अतः राजस्थान की कांग्रेस में सवाल उठ रहा है, क्या वे फिर राज्यसभा में ''रिपीट'' होंगे। पिछली बार उन्हें राजस्थान से राज्यसभा में भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी से राज्यसभा का टिकट देने का आग्रह किया था। पूर्व प्र.मंत्री के आग्रह को सोनिया गांधी टाल नहीं सकी थीं।**
- **अब मनमोहन सिंह की सीट के लिये राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के नेताओं में होड़ सी लगी है। हर नेता खुद को नहीं तो अपने ''आदमी'' को राज्यसभा में भेजना चाहता है।**
- **वैसे, राजस्थान से तीन राज्यसभा सदस्य, मनमोहन सिंह, किरोड़ी लाल मीणा व भूपेन्द्र यादव रिटायर हो रहे हैं। भूपेन्द्र यादव के रिपीट होने की संभावना है, पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से उनकी नजदीकी के कारण, पर, डॉ. मनमोहन सिंह व किरोड़ी लाल मीणा अपने स्वास्थ्य व प्रदेश में मंत्री बनने के कारण, शायद दोबारा राज्यसभा नहीं भेजे जायेंगे।**

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं।

कांग्रेस क्षेत्रों में प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि, क्या डा. साहिब को एक बार फिर राज्यसभा में स्थान दिया जाएगा, वो भी ऐसे समय में जब पार्टी के पास राज्यसभा में बहुत कम सीटें हैं।

राजस्थान के स्थानीय कांग्रेस नेता चाहते हैं कि, राज्य के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए, साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राजस्थान से राज्यसभा सीट पाने के लिए प्रयासरत हैं। हर कोई अपने प्रत्याशी के लिए जोर लगा रहा है।

जैसे ही, चुनाव आयोग ने राज्यसभा के लिए चुनावों की घोषणा की, वैसे ही राज्यसभा सीटों के लिए रस्साकशी शुरु हो गई है।

राजस्थान के तीन सांसद, डा. मनमोहन सिंह, किरोड़ीलाल मीणा और भूपेन्द्र यादव राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस को एक और भाजपा को दो सीटें मिलेंगी।

डा. मनमोहन सिंह वृद्ध हैं एवं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, इस कारण वो राज्यसभा में बहुत ही कम आते हैं। उन्हें घर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें घर मिला हुआ है। पिछली बार सोनिया गाँधी ने उन्हें राज्यसभा सीट इसलिए दी थी क्योंकि मनमोहन सिंह ने स्वयं ही इच्छा जताई थी कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। रोचक है कि, कांग्रेस ने सब बाहर वालों को राज्यसभा सीटें दीं, परिणामस्वरुप पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई।

किरोड़ी लाल मीणा विधायक के रूप में चुन लिए गए हैं और अब राजस्थान की भाजपा सरकार में मंत्री हैं।

भूपेन्द्र यादव भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा नेतृत्व के साथ करीबी संबंध के लिए जाने जाते हैं।

चुनाव आयोग ने आज 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की। चुनाव 27 फरवरी को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्र व राज्य सरकार जन जीवन घोटाले की जानकारी 3 सप्ताह में दें

जयपुर, 29 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए करीब नौ सौ करोड रुपए के घोटाले के मामले में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को अब तक की गई कार्रवाई

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने ''पब्लिक अगेंस्ट करप्शन'' की जनहित याचिका पर यह निर्देश दिये।**

की जानकारी पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जनहित याचिका में अधिवक्ता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश की पांचवी उल्टा-पलटी ने सोशल मीडिया को व्यस्त रखा व्यंगात्मक टिप्पणियों से

- **उदाहरण के लिये पांचवी बार राजभवन में शपथ लेने के बाद जब नीतीश अपना मफलर भूल आये शपथ स्थल पर, और पांच मिनट बाद मंच पर लौटे मफलर लेने तो, राज्यपाल चकित रह गये, क्योंकि अभी तो पन्द्रह मिनट भी नहीं हुए थे शपथ लिये।**

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ''पलटने की राजनीति'' ने सोशल मीडिया को व्यंगात्मक टिप्पणियों से व्यस्त रखा। फेसबुक, वॉट्सएप, इन्स्टाग्राम और एक्स के यूजर्स, कार्पोरेट जगत, सिनेमा व क्रिकेट का हवाला देते हुए एक दशक में पांचवीं बार ''यू टर्न'' करने के लिए मुख्यमंत्री को लक्ष्य बना रहे हैं।

उन्हें, ''पल्टू राम, पल्टू चाचा या पल्टू पुत्र'' कहते हुए नैटिज़न्स बड़े रचनात्मक रूप से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वाट्सएप के एक फारवर्ड में, ''उसने मुझे धोखा दिया'', का अनुवाद करते समय नीतीश के नाम को क्रिया बनाते हुए कहा, ''उसने मुझे नीतीश दिया।''

एक्स पर एक फॉरवर्ड में नीतीश से पांच कॉरपोरेट शिक्षाएं लेने को कहा गया, ''हमेशा लचीले रहो, सही समय पर पलट जाओ, अपने रास्ते कभी बंद नहीं करो, उसी कम्पनी में वापस जाने को तैयार रहो। और अंतिम शिक्षा है- जब तक हाथ में दूसरा ऑफर ना हो, तब तक वर्तमान पद कभी नहीं छोड़ो।

एक ''एक्स'' यूज़र ने क्रिकेट उपमा का उपयोग करते हुये अपना विचार व्यक्त किया कि, राजस्व और खेल की व्यापक अपील को बढ़ावा देने के लिए, बी.सी.सी.आई. क्रिकेट टूर्नामैंट के एक नए प्रारुप को शुरु करने की सोच रहा है। जिसमें, मैच के आधे समय के बाद, कप्तान को दूसरी टीम की कप्तानी करने की अनुमति होगी और इसका नाम ''नीतीश कप'' होगा।

एक अन्य ''एक्स'' यूज़र ने नीतीश को सी.ई.ओ. के लिए एक आदर्श

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'यह कोई रेलवे प्लेटफार्म नहीं है!'

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने वकील को बेअदबी के लिये फटकार लगायी

- **मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा, ''जैसे ही गाड़ी देखी, उस पर चढ़ने का प्रयास करता है यात्री, वैसे ही आप (वकील) भी बिना किसी इज़ाजत के ''आऊट ऑफ टर्न'' किसी भी समय मामला उठाना चाहते हैं।**

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक वकील को आउट-ऑफ-टर्न उल्लेख करने के लिए फटकार लगाई, यह कहते हुए कि, ''यह कोर्ट रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है।'' कोर्ट ने वकील से मामलों का उल्लेख करने के तरीके पर एक वरिष्ठ वकील के साथ चर्चा करने को कहा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी.वाय. चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील को चेतावनी दी कि, अदालत जुर्माना लगाएगी।

डी.वाय. चन्द्रचूड़ ने वकील से कहा, ''ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि, बस चढ़ गए, जो भी ट्रेन आ गई।''

जब वकील ने याचिका का जिक्र किया तो कोर्ट ने शुरू में ही यह जानने की कोशिश की कि, याचिका बैंच के समक्ष आज की सूची में है या नहीं।

कोर्ट ने आगे कहा, ''दोपहर 12 बजे आप उल्लेख किस तरह कर सकते हैं।''

वकील ने कहा कि, वह न्यायपालिका के खिलाफ नहीं है। लेकिन, चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा कि, मुद्दा यह नहीं है।

कोर्ट ने टिप्पणी की, ''आप इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटा में एक और छात्रा ने आत्महत्या की

कोटा, (निसं)। तमाम प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद कोटा में विद्यार्थियों की आत्महत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन की परीक्षा से पहले ही झालावाड़ की एक छात्रा ने सोमवार को सुसाइड कर लिया।

- **छात्रा 12वीं की परीक्षा तथा जॉइंट एन्ट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी।**
- **परीक्षा की तैयारी को लेकर वह लगातार तनाव में थी।**

वह परिवार के साथ कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके के मानपुरा में रहती थी। उसने अपने घर पर ही आत्महत्या की है। परिजन उसे एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अंतरिम बजट अधिकतर सरकार की आमदनी व खर्च का नीरस लेखा जोखा रहता है

इसलिये आजादी के बाद के प्रथम तीन बजट केवल देश की खाद्यान्न की कमी, विदेशी मुद्रा का घटता बैलेन्स तथा बढ़ती महंगाई को समर्पित थे

- **पर, 1992-93 के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, बजट देश की आर्थिक महत्वकांक्षाओं को प्रतिबिम्ब करने लगे थे, इसलिये आर.बी.आई. के तत्कालीन गवर्नर व पूर्व वित्त सचिव ने इस अवसर पर कहा था, ''अब हम अपनी महत्वकांक्षाओं (एम्बीशन) की बात कर सकते हैं।**
- **परन्तु इस वर्ष का केन्द्रीय बजट, जो कि लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या को पेश होगा, देश व सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक मैसेज देने की जिम्मेवारी भी निभायेगा।**
- **इसलिये बजट में महिला, यूथ व किसान को खुश करने का विशेष प्रयास होगा।**
- **साथ ही ए.आई. (ऑर्टिफिशल इंटैलीजैंस) पर फोकस करेगा।**

-अंजय रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जनवरी। आगामी बजट के बारे में अनुमान लगाना हमेशा पेचीदा होता है। बजट एक वित्त मंत्री की रणनीतिक आर्थिक सोच, एक प्रधानमंत्री के निर्देशों व मार्गदर्शन के साथ सरकार के सभी विभागों से भारी मात्रा में प्राप्त ''इनपुट'' का विश्लेषण करने के बाद तैयार किया जाता है। अंतिम उत्पाद हमेशा सभी मोर्चों पर एक ''अनिश्चित'' समझौता होता है।

लेकिन इस साल के अंतरिम बजट के बारे में निश्चित तौर पर कुछ व्यापक बाते कहीं जा सकती हैं। मौलिक रूप से एक अंतरिम बजट मौजूदा सरकार के राजस्व और व्यय का एक विवरण है और सरकार के आवश्यक कामकाज को जारी रखने के लिए विधायकों से अग्रिम मंजूरी देने के लिए सरकार की ओर से पेश की गयी एक याचिका है।

लेकिन फिर भी, अंतरिम बजट का संक्षेप में सिर्फ आवश्यक तथ्यों के साथ नहीं तैयार किया जाता है, विशेषकर जब यह निकट भविष्य में होने वाले चुनावों से पहले हो। बजट हमेशा वर्तमान उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटने और पहले कभी नहीं उठाए गए उत्कृष्ट कदमों के रूप में प्रदर्शित करने की कवायद बन जाता है।

लेकिन, भारत के कुछ अंतरिम बजट, जिसमें पहला बजट भी शामिल है, देश और अर्थव्यवस्था के समक्ष संकटों के बयान मात्र थे। स्वतंत्रता के तुरंत बाद के शुरुआती दिनों में, भारत के बजट निर्माण पर तीन चिंताएं हावी थीं। खाद्यान्न व विदेशी मुद्रा की कमी और उसके फलस्वरूप बढ़ती कीमतों ने कई वित्त मंत्रियों को परेशान कर दिया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)